



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2018/चैत्र 7, 1940

No. 200]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2018/CHAITRA 7, 1940

राज्य सभा सचिवालय

(संसद के सदनों की संयुक्त समिति)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2018

सा.का.नि. 311(अ).—संयुक्त समिति, संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् संसद सदस्य (निर्वाचन क्षेत्र भत्ता) नियम, 1986 जिन्हें धारा 9 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित और पुष्ट कर दिया गया है, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसद सदस्य (निर्वाचन क्षेत्र भत्ता) संशोधन नियम, 2018 है।
(2) ये 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होंगे।
- संसद सदस्य, (निर्वाचन क्षेत्र भत्ता) नियम, 1986 के नियम 2 में "पैंतालीस हजार रुपये प्रति मास" शब्दों के स्थान पर "सत्तर हजार रुपये प्रति मास" जो आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 की 43) की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खण्ड (v) के अधीन उपबंधित लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक के आधार पर 1 अप्रैल, 2023 से आरंभ होने वाले प्रत्येक पांच वर्ष में बढ़ जाएंगे" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[सं. आरएस. 11/2018/एमएसए]

जगमोहन सुन्दरियाल, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) तारीख 3 जनवरी, 1986 में अधिसूचना सं. सा.का.नि.14(अ), दिनांक 3 जनवरी, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार सा.का.नि. 970(अ), दिनांक 13 दिसम्बर, 2010 द्वारा संशोधन किया गया था।

RAJYA SABHA SECRETARIAT
(JOINT COMMITTEE OF HOUSES OF PARLIAMENT)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2018

G.S.R. 311(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of section 9 of the Salary, Allowances and pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), the Joint Committee, after consultation with the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Members of Parliament (Constituency Allowance) Rules, 1986, which have been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People, as required under sub-section (4) of section 9, namely:—

1. (1) These rules may be called the Members of Parliament (Constituency Allowance) Amendment Rules, 2018.
(2) They shall come into force from the 1st day of April, 2018.
2. In the Members of Parliament (Constituency Allowance) Rules, 1986 in rule 2, for the words “rupees forty-five thousand per mensem”, the words, figures and letters “rupees seventy thousand per mensem, which shall be increased in every five years commencing from the 1st April, 2023 on the basis of Cost Inflation Index provided under clause (v) of *Explanation* to section 48 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).” shall be substituted.

[No. RS. 11/2018/MSA]

JAGMOHAN SUNDRIYAL, Jt. Secy. & Financial Adviser

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 3rd January, 1986 *vide* notification number G.S.R. 14(E) dated the 3rd January, 1986 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 970(E) dated the 13th December, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2018

सा.का.नि. 312(अ).—संयुक्त समिति, संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के परामर्श से संसद सदस्य (कार्यालय व्यय भत्ता) नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, जिन्हें धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित और पुष्ट कर दिया गया है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसद सदस्य (कार्यालय व्यय भत्ता) संशोधन नियम, 2018 है।
(2) ये 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होंगे।
2. संसद सदस्य, (कार्यालय व्यय भत्ता) नियम, 1988 के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"3. कार्यालय व्यय भत्ते की रकम - (i) कोई सदस्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन प्रतिमास साठ हजार रुपए की दर से कार्यालय व्यय भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा, जिसमें से

(क) बीस हजार रुपए लेखन सामग्री मर्दों और डाक व्यय को चुकाने के लिए होंगे;

(ख) लोक सभा या राज्य सभा सचिवालय उन व्यक्ति(व्यक्तियों) को चालीस हजार रुपए तक का संदाय कर सकेगा जिन्हें सदस्य द्वारा सचिवालय सहायता अभिप्राप्त करने के लिए नियोजित किया जाए और ऐसा एक व्यक्ति सदस्य द्वारा सम्यकतः प्रमाणित कम्प्यूटर साक्षर होगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन कार्यालय व्यय भत्ते में 1 अप्रैल, 2023 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक पांच वर्ष में आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) में उपबंधित लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी।"

[सं. आरएस. 11/2018/एमएसए]

जगमोहन सुन्दरियाल, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1098(अ), तारीख 25 नवम्बर, 1988 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 972(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2010 द्वारा किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2018

G.S.R. 312(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of section 9 of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), the Joint Committee, after consultation with the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Members of Parliament (Office Expense Allowance) Rules, 1988, which have been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People, as required under sub-section (4) of section 9, namely:

1. (1) These rules may be called the Members of Parliament (Office Expense Allowance) Amendment Rules, 2018.
- (2) They shall come into force from the 1st day of April, 2018.
2. In the Members of Parliament (Office Expense Allowance) Rules, 1988, for rule 3, the following rule shall be substituted namely:

“3. Amount of Office Expense Allowance. – (1) A member shall be entitled to receive the office expense allowance under section 8 of the Act, at the rate of rupees sixty thousand per mensem, out of which-

- (a) rupees twenty thousand shall be for meeting expenses on stationery items and postage; and
- (b) the Lok Sabha or the Rajya Sabha Secretariat may pay upto rupees forty thousand to the person(s) as may be engaged by a Member for obtaining secretarial assistance and one such person shall be computer literate duly certified by the Member.”

(2) The Office Expense Allowance under sub-rule (1) shall be increased every five years commencing from the 1st April, 2023, on the basis of Cost Inflation Index provided under clause (v) of *Explanation* to section 48 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).”

[No. RS. 11/2018/MSA]

JAGMOHAN SUNDRIYAL, Jt. Secy. & Financial Adviser

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 1098(E) dated the 25th November, 1988 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 972(E) dated the 13th December, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2018

सा.का.नि. 313(अ).—संयुक्त समिति, संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार से परामर्श के पश्चात्, आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956 में ऐसे और संशोधन करने के लिए, जिन्हें

धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन यथाअपेक्षित राज्य सभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित और पुष्ट कर दिया गया है, नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होंगे।

2. आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956 में, --

(क) नियम (2) के उपनियम (3) में प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु सदस्यों को क्रमशः टिकाऊ फर्नीचर की बाबत अस्सी हजार रुपये और गैर-टिकाऊ फर्नीचर की बाबत बीस हजार रुपये की विद्यमान धनीय सीमा के भीतर रहते हुए प्रभार मुक्त फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के अधीन उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक से आधार पर 1 अप्रैल, 2023 से आरंभ होने वाले प्रत्येक पांच वर्ष में बढ़ जाएंगे";

(ख) नियम 4 में, उपनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतर्लिखित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(8) 1 अगस्त, 2006 से कोई सदस्य ब्राडबैंड इंटरनेट सुविधा का, या तो प्रति वर्ष दस हजार अभ्यर्पित काल इकाई के बदले 512 किलोबाइट प्रति सैकेंड (केबीपीएस) गति की दर से अधिकतम सौ गीगाबाइट्स (100 जीबी) डाटा डाउनलोड के साथ उपभोग किए गए प्रत्येक अतिरिक्त मेगाबाइट के लिए रु. 0.50 पैसे प्रति मेगाबाइट या प्रति वर्ष दस हजार अभ्यर्पित काल के बदले 256 किलोबाइट प्रति सैकेंड (केबीपीएस) गति की दर से असीमित डाटा डाउनलोड के विकल्प का उपयोग कर सकेगा।

स्पष्टीकरण - इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, "ब्राडबैंड इंटरनेट सुविधा" प्रत्येक बिंदु को पृथक्कृत: लागू होगी जहां सदस्य कोई कनेक्शन लेना चाहेगा और सदस्यों के विद्यमान लैंडलाइन कनेक्शन पर ब्राडबैंड कनेक्शन का उपबंध करने के लिए पद्धति उन्हें उपलब्ध कराए जाने वाले पब्लिक स्विचड टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन) की विद्यमान पद्धति के अनुरूप होगी और ब्राडबैंड कनेक्शन का अर्थान्वयन पब्लिक स्विचड टेलीफोन लाइन पर मूल्य वर्द्धित सेवा के रूप में किया जाएगा।

(9) कोई सदस्य 1 सितंबर, 2015 से 31 दिसंबर, 2016 तक, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से दिल्ली में अपने निवास पर वाई फाई सेवाओं सहित फाइबर से होम (एफटीटीएच) पर उच्च गति ब्राडबैंड का लाभ ले सकेगा और वह प्रति माह एक हजार सात सौ रुपये की अधिकतम सीमा तक संदाय करने का दायी नहीं होगा, इसको सीधे महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को इस सुविधा के प्रभार के लिए संदत्त किया जाएगा।

(10) कोई सदस्य 1 जनवरी, 2017 से महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से दिल्ली में अपने निवास पर वाई फाई सेवाओं सहित फाइबर से होम (एफटीटीएच) पर उच्च गति ब्राडबैंड का लाभ ले सकेगा और वह प्रति माह दो हजार दो सौ रुपये की अधिकतम सीमा तक संदाय करने का दायी नहीं होगा, इसको सीधे महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को इस सुविधा के प्रभार के लिए संदत्त किया जाएगा।"

[सं. आरएस. 11/2018/एमएसए]

जगमोहन सुन्द्रियाल, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1972(अ), तारीख 8 मई, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.748(अ) तारीख 12 दिसंबर, 2006 द्वारा संशोधित किए गए थे।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रस्ताव किया गया है कि, अन्य बातों के साथ, 1 अगस्त, 2006 से सदस्यों को दिए गए लैंडलाइन कनेक्शन पर प्रति वर्ष अभ्यर्पित 10,000 काल के बदले संसद सदस्यों को ब्राडबैंड इंटरनेट सुविधा दी जाए। ब्राडबैंड इंटरनेट सुविधा संसद सदस्यों को 1 अगस्त, 2006 से दी जा रही है और इसको संशोधनों द्वारा विनियमित किया जाना है। सदस्यों के निवासीय क्षेत्रों में फाइबर से होम (एफटीटीएच) पर उच्च गति ब्राडबैंड उपलब्ध कराने के लिए विद्यमान ब्राडबैंड सुविधा 1 सितंबर, 2015 से 31 दिसंबर, 2016 तक एक हजार सात सौ रुपए के मासिक टैरिफ प्लान के साथ और 1 जनवरी, 2017 से दो हजार दो सौ रुपए के एक मासीय टैरिफ प्लान के साथ वाई फाई जोन का सृजन का भी प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावों को भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए आवश्यक संशोधन करने आवश्यक हैं। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव देने से कोई भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2018

G.S.R. 313(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of section 9 of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), the Joint Committee, after consultation with the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956, which have been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People, as required under sub-section (4) of section 9, namely:

1. (1) These rules may be called the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Amendment Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the 1st day of April, 2018.
2. In the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956, -

- (a) in rule 2, in sub-rule (3), for the first proviso, the following proviso shall be substituted namely:-

“Provided that furniture shall be made available free of charge to the Members within the existing monetary ceiling of rupees eighty thousand in respect of durable furniture and rupees twenty thousand for non-durable furniture respectively, which shall be increased every five years commencing from the 1st April, 2023, on the basis of Cost Inflation Index provided under clause (v) of *Explanation* to section 48 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).”

- (b) in rule 4, after sub-rule (7), the following sub-rules shall be inserted namely:-

“(8) With effect from the 1st August, 2006, a Member may avail broadband internet facility with option either to have a maximum of hundred gigabyte (100 GB) data download at the rate of 512 kilobits per second (kbps) speed against ten thousand surrendered call units per annum with Rs.0.50 paise per megabyte (MB) on every additional megabyte (MB) consumed or unlimited data download at the rate of 256 kilobits per second (kbps) speed against ten thousand surrendered call units per annum.

Explanation.— For the purpose of this sub-rule, the “broadband internet facility” shall apply separately to each point where the

Member would like to have a connection and modality for provisioning of broadband connectivity on the existing landline connections of Members shall be akin to the existing practice of provisioning of public switched telephone network (PSTN) connections to them and the broadband connection shall be construed as value added service on the existing public switched telephone line.

(9) With effect from the 1st September, 2015 to the 31st December, 2016, a Member may avail high speed broadband on the Fibre to the Home (FTTH) with wi-fi services at his residence in Delhi from the Mahanagar Telephone Nigam Limited and shall not be liable to make payment up to a maximum of rupees one thousand seven hundred per mensem, which shall be paid directly to the Mahanagar Telephone Nigam Limited towards charges for this facility.

(10) With effect from the 1st January, 2017, a Member may avail high speed broadband on the Fibre to the Home (FTTH) with wi-fi services at his residence in Delhi from the Mahanagar Telephone Nigam Limited and shall not be liable to make payment up to a maximum of rupees two thousand two hundred per mensem, which shall be paid directly to the Mahanagar Telephone Nigam Limited towards charges for this facility.”.

[No. RS. 11/2018/MSA]

JAGMOHAN SUNDRIYAL, Jt. Secy. & Financial Adviser

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, extraordinary, Part III, Section 3, *vide* notification number S.R.O. 1972(E) dated the 8th May, 1956 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 748(E) dated the 12th December, 2006.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has been proposed, *inter alia* to provide broadband internet facility to the Members of Parliament against ten thousand surrendered call units per annum on landline connected to the Members with effect from 1st August, 2006. The facility of broadband internet is being provided to the Members of Parliament from the 1st August, 2006 and has to be regularized by the amendments. It has also been proposed for creation of wi-fi zone in the Members residential areas for providing high speed broadband on the Fibre to the Home with monthly tariff plan of rupees one thousand seven hundred only with effect from the 1st September, 2015 to 31st December, 2016, in addition to the existing broadband facility and one monthly tariff plan of rupees two thousand two hundred only with effect from the 1st January, 2017. Necessary amendments are required to give retrospective effect to the proposals. It is certified that none will be adversely affected by giving retrospective effect to these amendments.